प्रेषक,

सी०एम०एस० बिष्ट, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुमाग-02

देहरादूनः दिनांक

🔊), मार्च, 2014:

विषय— वित्तीय वर्ष 2013—14 में मत्स्य विभाग को आयोजनेत्तर पक्ष के निदेशन एवं प्रशासन में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2348/लेखा/बजट/नान—प्लान/2013—14, दिनांक 06 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रू० 18.50 लाख (रू० अटारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी०एम०—9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- 1. निदेशक, मत्स्य द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फाँट कर तत्काल जिला—स्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा। फांट इस प्रकार की जायेगी कि निदेशालय एवं जनपदों में कार्मिकों की संख्या एवं देयता को मध्य नजर रखते हुए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाये ऐसा न हो कि एक जनपद में अधिक बजट दे दिया जाय, जबकि अन्य जनपदों में बजट की कमी रह जाये।
- 2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम0-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 4. व्यय करते समय मितव्यता के संबंध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतन आदि मदों में अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक / मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
- 6. जो बिल कोषागार को भुंगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

- 7. सुनिश्चित किया जायेगा कि (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग—1 के पैरा—162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण—वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के भीतर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी०सी०) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।
- 2— उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 में अनुदान संख्या—28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2405—मछली पालन—00—आयोजनेत्तर—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा संलग्नक—बी०एम0—9 के कॉलम संख्या—1 में दर्शायी गई मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या—100NP/XXVII-4/2014 दिनांक 20 मार्च, 2014 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न-बी०एम0-9



संख्या- \5 - (1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6. निर्देशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह) उप सचिव।